

भारत में ऑनर कलिगि

परलिमिस् के लयि: [खाप पंचायत](#), [राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो](#), [अनुच्छेद 21](#)

मेन्स के लयि: जात-आधारति हसिा को जारी रखने में परिवार और समुदाय की भूमिका, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में ऑनर कलिगि

[स्रोत: द हद्दि](#)

चर्चा में क्यों?

भारत में जातव्यवस्था समाज में गहनता से समाहित है और [ऑनर कलिगि](#) का प्रयोग तेज़ी से जातगित पदानुक्रम को लागू करने के साधन के रूप में किया जा रहा है, विशेष रूप से अंतरजातीय ववाहों के खिलाफ।

- तमलिनाडु एवं अन्य राज्यों में हुई हालिया घटनाएँ इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि कैसे परिवार और समुदाय ऐसी हसिा को वैध ठहराते हैं तथा संवैधानिक मूल्यों को कमज़ोर करते हैं।

ऑनर कलिगि क्या है?

- **परचिय:** ऑनर कलिगि हसिा का वह रूप है, जो प्रायः हत्या के रूप में सामने आता है और अधिकतर मामलों में परिवार के सदस्य ही इसे अंजाम देते हैं। इसका शकार वे युगल बनते हैं जनिहें यह माना जाता है कि उन्होंने जात, समुदाय या लैंगिक मानदंडों की अवहेलना कर परिवार का अपमान किया है। इसमें जात-अंतरववाह (Caste endogamy) और गोत्र-बहर्ववाह (Gotra exogamy) जैसे नयिमों का उल्लंघन भी शामिल है।
- **ऑनर कलिगि से नपिटने में कानून की भूमिका:**
 - **संवैधानिक सुरक्षा:** अनुच्छेद 14 (समता का अधिकार), अनुच्छेद 15 (भेदभाव को प्रतर्बिधति करने का अधिकार), अनुच्छेद 19 (संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता) तथा अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) ऑनर कलिगि के खिलाफ संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।
 - **सांवधिकि प्रावधान:** ऑनर कलिगि को भारतीय दंड संहतिा (अब [भारतीय न्याय संहतिा](#)) के अंतर्गत हत्या की श्रेणी में रखा गया है।
 - [हद्दि ववाह अधनियिम, 1955](#) ने अंतरजातीय और सगोत्र ववाह की अनुमति दी तथा जात-अंतरववाह ववाह प्रथाओं को चुनौती दी।
 - [वशिष ववाह अधनियिम, 1954](#) खाप पंचायतों के वरिध का सामना करने वाले अंतरजातीय ववाहों को मान्यता देता है।
- **न्यायकि दृष्टांत (Judicial Precedents):**
 - **लता सहि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006):** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अंतरजातीय ववाह वैध है और नरिदेश दिया कि पुलिस को ऐसे दंपत्तयिों की सुरक्षा करनी चाहयि।
 - **अनुमुगम सर्वई बनाम तमलिनाडु राज्य (2011):** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि [खाप पंचायतें अवैध हैं](#)। अंतरजातीय दंपत्तयिों के वरिद्ध जारी आदेशों को रद्द किया जाना चाहयि।
 - **वकिास यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2016):** सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दिया कि सम्मान के नाम पर महिलाओं की साथी चुनने की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
 - **शक्तववाहनी बनाम भारत संघ (2018):** सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनर क्राइम की परिभाषा को वसितृत किया और माना कि वयक्तगित चुनाव गरमिा (अनुच्छेद 19 व 21) का हसिा है।
 - न्यायालय ने राज्यों को नरिदेश दिया कि वे सुरक्षा आश्रय गृह स्थापति करें, जातगित सभाओं पर नगरिानी रखें और लापरवाही बरतने वाले अधिकारयिों को उत्तरदायी ठहराएँ।
 - **शफीन जहान बनाम अशोकन के.एम. एवं अन्य (2018):** अनुच्छेद 21 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने किसी वयक्त के अपनी पसंद के वयक्त से ववाह करने के अधिकार को बरकरार रखा।
- **ऑनर कलिगि के परिणाम:** यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, जो सीधे तौर पर [अनुच्छेद 21](#) और अनुच्छेद 19 जैसे मौलिक अधिकारों पर आघात करता है।
 - ये **लैंगिक अन्याय** को बनाए रखते हैं, क्योंकि महिलाएँ असमान रूप से इसका शकार बनती हैं, साथ ही जातगित पदानुक्रम को मटिाने के बजाय और मज़बूत करते हैं।

- ऐसे अपराध **लोकतंत्र और वधिके शासन** को कमजोर करते हैं, क्योंकि समानांतर जातीय परिधि संवेधानिक न्यायालयों की सत्ता को चुनौती देती हैं।
- **वधिके और राजनीतिक नहितार्थों से परे**, ऑनर कलिगि से गहरा मनोवैज्ञानिक आघात पहुँचता है, जिससे युवाओं में जातियाँ धर्म से बाहर विवाह करने के प्रति **भय, असुरक्षा तथा झझक** उत्पन्न होती है।
- यह न केवल सामाजिक प्रगतिको रोकता है बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नगरानी को भी आकर्षित करता है, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की छवि धूमिल होती है।

भारत में ऑनर कलिगि को बढ़ावा देने वाले कारक कौन-से हैं?

- **परिवार की भूमिका:** परिवार परंपरागत रूप से जातगत मानदंडों को लागू करने का प्रमुख माध्यम रहा है।
 - शहरीकरण, शिक्षा और आधुनिक विचारों के संपर्क के बावजूद, जात आज भी बनी हुई है क्योंकि **परिवार-केंद्रित समाजीकरण** अनुष्ठानों, विवाह व्यवस्थाओं, रीति-रिवाजों तथा वरिसत में मल्लि पूरवाग्रहों के माध्यम से होता है।
 - **बच्चे बचपन से ही जातगत सीमाओं को आत्मसात कर लेते हैं**, जिससे उनके सामाजिक संबंध, विवाह संबंधी नरिणय और 'सम्मान' की धारणाएँ प्रभावित होती हैं।
 - परिवारों के माध्यम से जात का यह प्रवर्तन, अंतरजातीय संबंधों को हसिक प्रतिक्रिया के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बना देता है।
- **सामुदायिक प्रवर्तन और सामाजिक दबाव:** समुदाय और अनौपचारिक नकियाय, जैसे **खाप पंचायतें**, प्रायः जात-अंतरविवाह के नयिमाँ को चुनौती देने वालों के खिलाफ हसिा को स्वीकृत देते हैं या मौन समर्थन प्रदान करते हैं।
 - सामाजिक मानदंड और साथियों का दबाव इस विचार को और मज़बूत करता है कि जातगत नयिमाँ के उल्लंघन को दंडित किया जाना चाहिये।
 - **सामाजिक प्रगतिका वरिधाभास:** तमलिनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और केरल जैसे वे राज्य, जहाँ दलित सशक्तीकरण अपेक्षाकृत अधिक है, वहाँ अंतरजातीय विवाह भी अधिक दर्ज होते हैं तथा साथ ही ऑनर कलिगि की घटनाएँ भी अधिक सामने आती हैं।
 - यह हसिा उन प्रदेशों में ज़्यादा दिखाई देती है जहाँ जातगत व्यवस्था को अस्थिरता का अनुभव होता है, न कि उन प्रदेशों में जहाँ यह व्यवस्था सबसे अधिक स्थायी और गहरी है।
 - ऑनर कलिगि प्रायः तब होती है जब वंचित समुदाय, विशेष रूप से दलित, शिक्षा, रोज़गार और सामाजिक गतिशीलता के माध्यम से सशक्त होते हैं। अंतरजातीय संबंध, विशेषकर दलित पुरुषों और प्रभुत्वशाली जातियों की महिलाओं के बीच, स्थापित **जातगत पदानुक्रम** को चुनौती देते हैं तथा इसी के परिणामस्वरूप हसिा होती है।
- **वरिधाभासी सार्वजनिक और नज़ी दृष्टिकोण:** तमलिनाडु जैसे क्षेत्रों में जातगत हसिा का सार्वजनिक रूप से वरिध किया जाता है, कति नज़ी दृष्टिकोण और सोशल मीडिया पर प्रायः जातगत नयितरण तथा हसिा का महमिमंडन किया जाता है।
 - **डिजिटल मंचों की गुमनामी जातगत गौरव को बढ़ावा देती है** और वरिसत में मल्लि सामाजिक शक्ति खोने के भय को और प्रबल करती है, जिससे अंतरजातीय विवाहों के प्रति वैमनस्यता को बढ़ावा मलित है।
- **कमज़ोर कानूनी प्रवर्तन:** **खाप (उत्तर भारत) और कट्टा (दक्षिण भारत)** स्वयंभू ग्राम सभाएँ हैं जनि पर प्रभावशाली जातके पुरुषों का प्रभुत्व होता है। ये परिधि परंपरा का हवाला देकर हसिा का सहारा लेते हैं और पतिसत्तात्मक व्यवस्था को मज़बूती प्रदान करते हैं।
 - ऑनर कलिगि को भारत में एक अलग अपराध के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)** इसे 'हत्या' के अंतर्गत दर्ज करता है, जिससे इसकी पहचान और वर्गीकरण कठिन हो जाता है।

भारत में बदलती सामाजिक गतिशीलता का भविष्य में जातव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

- **बदलती सामाजिक गतिशीलता:** दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों में विवाह दर में गिरावट तथा परिवार संरचना के बदलते स्वरूप अब शहरी भारत में भी दिखाई देने लगे हैं।
 - शहरी युवा पारंपरिक पारिवारिक दायित्वों की अपेक्षा व्यक्तिगत विकास, आत्मनरिभरता और भावनात्मक सुख-समृद्धि को अधिक प्राथमिकता देने लगे हैं।
- **जातव्यवस्था के भावी नहितार्थ:** भारत की जातव्यवस्था एक नरिणायक दौर से गुजर रही है, जहाँ एक ओर हसिक प्रतिक्रियाएँ हैं तो दूसरी ओर लोकतांत्रिक प्रतिरोध भी उभर रहा है।
 - **जैसे-जैसे परिवार का प्रभाव कमज़ोर होता है**, वैसे-वैसे जातगत मानदंडों और सम्मान-आधारित अपेक्षाओं का पालन चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, जिससे धीरे-धीरे उस सांस्कृतिक ढाँचे का क्षरण हो रहा है जो जातको बनाए रखता है।
 - इसके लिये पारदर्शी संवाद, वैकल्पिक आख्यान और सामाजिक प्राथमिकताओं में बदलाव आवश्यक है, जो संस्थानों तथा सामाजिक मूल्यों पर जातके प्रभुत्व को कमज़ोर कर सकते हैं।

ऑनर कलिगि से निपटने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- **स्वतंत्र कानून बनाना:** ऑनर कलिगि को लेकर एक अलग राष्ट्रीय कानून बनाया जाए, जिसे सामान्य हत्या के कानूनों से अलग रखा जाए, ताकि त्वरित और लक्षित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
 - अपराधियों के खिलाफ गवाही देने वालों के लिये **गवाह संरक्षण कार्यक्रम** लागू किए जाएँ और पुलिस अधिकारियों व न्यायाधीशों को ऑनर कलिगि, जातगत हसिा तथा लैंगिक संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण दिया जाए।
 - ऑनर कलिगि से जुड़े मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिये विशेष **फास्ट-ट्रैक कोर्ट** की स्थापना की जाए, ताकि समय पर न्याय मल्लि सके।
- **आश्रय गृह:** विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पीड़ितों और ऑनर कलिगि के खतरे में पड़े व्यक्तियों के लिये अधिक आश्रय गृह तथा सहायक तंत्र स्थापति किये जाएँ।
- **जन-जागरूकता अभियान:** धार्मिक व जातगत प्रतिनिधियों सहित सामुदायिक अभिकर्त्ताओं को साथ लेकर, ऑनर-आधारित हसिा के दुष्परिणामों पर जागरूकता फैलाने और सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देने हेतु अभियान चलाए जाएँ।

- **शैक्षिक कार्यक्रम:** विद्यालयों और महाविद्यालयों में **लैंगिक समानता, मानवाधिकार तथा ऑनर-आधारित हिंसा** के परिणामों पर शिक्षा दी जाएँ, ताकि पारंपरिक व कठोर मानसिकताओं को चुनौती दी जा सके।
- **डिजिटल वैकल्पिक अध्ययन:** सोशल मीडिया का उपयोग कर सकारात्मक अभियान चलाए जाएँ, जो **व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और प्रेम** का समर्थन करें।

नबिर्कष

ऑनर कलिगि से नपिटने के लयि कानूनी, सामाजकि और सांस्कृतकि सुधारों के साथ-साथ सामुदायकि भागीदारी की भी आवश्यकता है। शकिषा, आर्थकि अवसरों और कानूनी सुरक्षा के माध्यम से व्यक्तियों, वशिषकर महिलाओं को सशक्त बनाना हसिा के चकर को तोड़ने तथा समानता को बढ़ावा देने की कुंजी है।

222222 222222 222222:

प्रश्न. “भारत में ऑनर कलिगि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जात-आधारित नियंत्रण की नरितरता को दर्शाती है।” संवैधानकि सुरक्षा उपायों के संदर्भ में चर्चा कीजिये।

<

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

मेन्स

प्रश्न. “जातवियवस्था नई-नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है। अतः भारत में जातवियवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है।” टपिणी कीजिये। (2018)

प्रश्न. खाप पंचायतें संवधानेतर प्राधिकरणों के तौर पर प्रकार्य करने, अक्सर मानवाधिकार उल्लंघनों की कोर्ट में आने वाले नरिणियों को देने के कारण खबरों में बनी रही हैं। इस संबंध में स्थिति को ठीक करने के लिये विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा की गई कार्रवाइयों पर समालोचनात्मक चर्चा कीजिये। (2015)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/honour-killings-in-india>